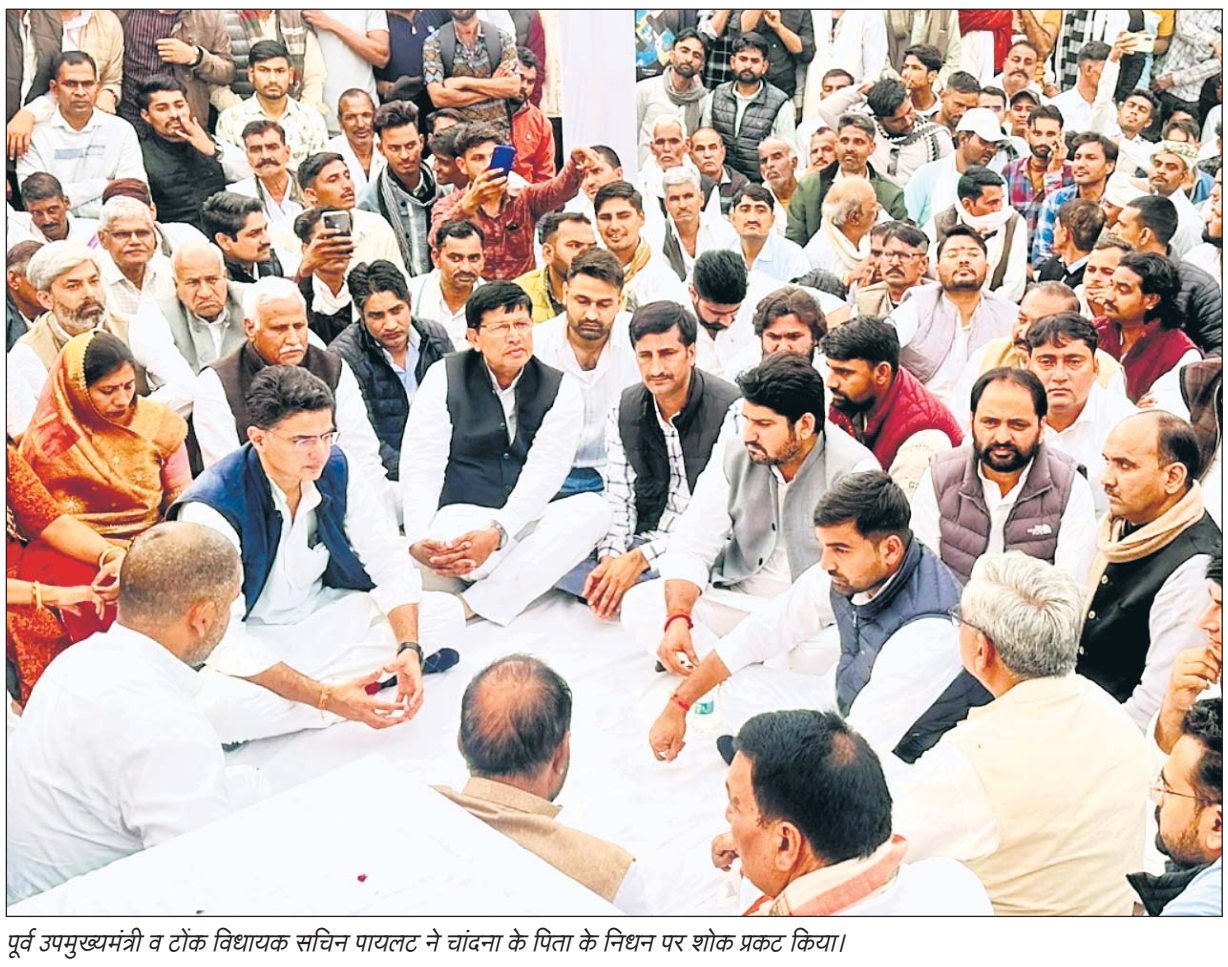

पूर्व उपमुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने चांदना के पिता के निधन पर शोक प्रकट किया।

सचिन पायलट चांदना के पिता के निधन पर शोक प्रकट करने बूंदी पहुंचे

■ बाद में पायलट को बगल में बैठा कर अशोक चांदना के गाड़ी चलाने को, कांग्रेस कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

बूंदी, 31 जनवरी (निस)। पूर्व उपमुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट बुधवार को एक दिवसीय बूंदी दौरे पर रहे। जहाँ उन्होंने पूर्व मंत्री अशोक चांदना के पिता के निधन पर श्योपुरिया की बावडी स्थित चांदना के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की।

सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुँचे थे। पेच की बावडी, हिंडौली, बड़ा नयागांव, बहादूर सिंह सर्किल पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से पायलट का स्वागत किया। इसके बाद पायलट श्योपुरिया की बावड़ी स्थित चांदना पैलेस पहुंचे, और पूर्व मंत्री चांदना के पिता, गुर्जर समाज जिलाध्यक्ष देवलाल चांदना के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की व शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।

बैठक के उपरांत सचिन पायलट जब चांदना पैलेस से बाहर निकले तो लोगों को अलग ही नजारा देखने को मिला। पायलट अशोक चांदना के साथ एक गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए। गाड़ी को अशोक चांदना स्वयं चला रहे थे तथा पायलट बगल की सीट पर बैठे थे।

राजनीति में एक दूसरे के पूरक व कट्टर विरोधी माने जाने वाले अशोक चांदना व सचिन पायलट का एक साथ एक गाड़ी में बैठकर यूं आना प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। दोनों नेता गुर्जर समाज से हैं। पायलट द्वारा गहलोत सरकार को गिराने के समय अशोक चांदना गहलोत के तारणहार बने थे तब से ही दोनों में मनमुटाव राजनीतिक मंचों पर कई बार साफ साफ देखने को मिल चुका है। जयपुर से बूंदी तक के दौरे के बीच सचिन पायलट के काफिले में सैकड़ों की संख्या में कारें शामिल थी। जिसमें प्रदेश भर से आए पूर्व मंत्री , विधायक ,कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे।

ई.आर.सी.पी. के बारे में बोलते हुए पायलट ने कहा कि, जो इतने सालों से मामला लंबित था, उसको सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह समाप्त करके जनता में जो भ्रम फैलाने का काम किया है, उससे लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे।

पायलट ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय के बाद हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो सबने उसका स्वागत किया। राम किसी एक देश के नहीं हैं, उन्हें सीमित कर देना और उसे राजनितिक दृष्टिकोण से देखना, मैं उसको गलत मानता हूं।

उन्होंने कहा कि, पब्लिक इशूज़ को लेकर जज़्बातों से परे हटकर वास्तविकता में चुनाव लड़ना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनावों में बहुत बेहतर होगा।

'ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की व्यवस्था की जाए'

वाराणसी, 31 जनवरी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला न्यायालय ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण की ओर स्थित तहखाने के अंदर विराजमान मूर्तियों की पूजा और राग भोग की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया।

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा की अदालत ने शैलेन्द्र कुमार पाठक बनाम अंजुमन इंतजामिया कमेटी व अन्य के मामले में सुनवाई के बाद आदेश में कहा, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी और रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि, वे निपटान भूखंड संख्या 9130 की इमारत के दक्षिण की ओर बेसमेंट में स्थित मूर्तियों की पूजा, राग-भोग निर्दिष्ट पुजारी से कराये जो कि वाद संपत्ति है और इसके लिए सात दिनों के भीतर लोहे की बाड़ आदि की उचित व्यवस्था करें।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि, 2023 में शैलेन्द्र कुमार पाठक ने अर्जी दाखिल की थी कि, मंदिर के दक्षिण तरफ के तहखाने में स्थित मूर्ति की पूजा की जा रही थी लेकिन दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास को बैरिकेडिंग एरिया में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके कारण उक्त परिसर का राग-भोग का अनुष्ठान भी बंद हो गया।

मुख्यमंत्री भजन लाल रोलसाहबसर से मिलने गये

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोलसाहबसर से मिलकर उनके बड़े भाई के निधन पर शोक प्रकट किया।

■ उन्होंने रोलसाहबसर के बड़े भाई के निधन पर शोक प्रकट किया और श्री क्षत्रिय युवक संघ के दिल्ली सम्मेलन पर विस्तार से चर्चा की।

■ चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर तथा प्रताप फाउण्डेशन के संयोजक महावीर सिंह सरबड़ी भी इस मुलाकात के समय उपस्थित थे।

जयपुर, 31 जनवरी (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संघ शक्ति पहुंचकर श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोलसाहबसर से भेंट कर उनके बड़े भाई (स्व.दुर्जन सिंह) के देहांत पर शोक प्रकट किया। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर व श्री प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी भी इस दौरान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने तनसिंह की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि, राजपूत समाज का भाजपा के विशाल स्वरूप को बनाने में विशेष योगदान रहा है। राजस्थान में जनसंघ के समय से भाजपा को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में राजपूत समाज का प्रयास सराहनीय रहा। वर्तमान समय में भी सरकार को बनाने में राजपूत समाज ने एक तरफा मतदान किया, उसी का परिणाम है कि सरकार बनी।

प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने मुख्यमंत्री को बताया कि, राजस्थान के 90 प्रतिशत राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। पार्टी द्वारा 26 टिकट दिए गए उनमें से समाज के 16 विधायक पार्टी से जीतकर आये।

जीत का प्रतिशत टिकट के आधार पर 62 प्रतिशत रहा उसके बावजूद मात्र 3 मंत्री बनाये गये जबकि इससे पूर्व 4-5 मंत्री बनते रहे हैं। सरवड़ी ने राजपूत समाज द्वारा सरकार बनाने में दिए योगदान के अनुरूप मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने आगामी विस्तार में ध्यान रखने का आश्वासन दिया।

आरक्षण के सरलीकरण के विषय में सरवड़ी ने केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा लिखित प्रस्ताव देने का आग्रह किया जिस पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। मुख्यमंत्री को सरकार में राजपूत समाज के अधिकारियों की हो रही उपेक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई।

भगवान सिंह ने राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए कार्य करने का आग्रह किया जिसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने बार-बार मार्गदर्शन देते रहने का आग्रह किया।

हनुमानगढ़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिनट तक बारिश का दौर चला। जयपुर में शाम को कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि शहर का तापमान अधिकतम 21 डिग्री तक रहा।

जयपुर शहर में सुबह मौसम साफ रहा और हल्की धूप रही, लेकिन दोपहर बाद आसमान पर बादलों की आवाजाही रही। इसे देखते हुए एक-दो दिन में यहां भी मावठ की संभावना बन रही है। बारिश ने उन किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है, जिनके खेतों में सरसों की फसल पककर तैयार हो गई या कटाई शुरू हो गई है। हालांकि गेहूं, चना और जौ की फसल के लिए यह बारिश अच्छी मानी जा रही है।

मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक, राधेश्याम शर्मा के अनुसार, फरवरी में राज्य के उत्तरी भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है, बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 3-4 फरवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश होने की प्रबल संभावना है।

सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित वरिष्ठ नेताओं का चयन किया जा रहा है।

कांग्रेस, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों और प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्षों को भी मैदान में उतार सकती हैं, जहां वे हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा में बहुमत नहीं प्राप्त कर सके थे।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है और इसी तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

जिन नामों पर विचार किया जा रहा है, उनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण और नाना पटोले, गुजरात के शक्ति सिंह गोहिल और अर्जुन मोडवाडिया, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए हैं कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि वो पहले से ही राज्यसभा सदस्य हैं।

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि, वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए पहले ही बता दिया गया है क्योंकि, उनके चुनाव लड़ने से, उनके पडौसी निर्वाचन क्षेत्रों में भी पार्टी को लाभ मिलेगा।

कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति, "इंडिया ब्लॉक" के दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत करने के साथ साथ, नामों पर अंतिम निर्णय लेगी।

'गेहूं खरीद पर अतिरिक्त बोनस के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करें'

■ खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की विधानसभा में घोषणाओं की त्वरित क्रियान्वति के निर्देश दिये।

जयपुर, 31 जनवरी (का.सं.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने 'राजस्थान कृषक समर्थन योजना' के अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की प्रभावी क्रियान्विति के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में अभिभाषण पर बहस के जवाब में इस संबंध में घोषणा की थी।

गोदारा ने कहा कि, राज्य सरकार अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि, उचित मूल्य की सभी दुकानों पर भौतिक सत्यापन के लिए आइरिस मशीनें स्थापित की जाएं जिससे पात्र लोगों को लाभ लेने में सहूलियत हो।

गोदारा बुधवार को मंत्रालय भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और उपभोक्ता मामलात विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। खाद्य मंत्री गोदारा ने कहा कि, इससे प्रदेश के किसानों को गेहूं की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रूपए प्रति क्विंटल के साथ 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि, इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें।

गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के वो परिवार, जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के हों या विशेष दिव्यांगजन हों, ऐसे परिवारों को राशन की निःशुल्क होम डिलीवरी की जाएगी

गोदारा ने उपभोक्ता मामलात विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि, प्रदेश में उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सोशल, प्रिंट व लोक मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक जागरूकता फैलाई जाए।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, विशिष्ट शासन सचिव राजेन्द्र विजय, निगम के प्रबन्ध निदेशक परमेश्वर लाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

हेमन्त सोरेन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सत्तारुढ़ गठबंधन ने नए नेता की अगुवाई में सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी थी। गठबंधन के तमाम विधायक बुधवार सुबह से सीएम हाउस में जमा थे। मंगलवार को सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय कर लिया गया था कि, उनकी गिरफ्तारी की नौबत आने पर नए नेता की अगुवाई में सरकार के लिए दावा पेश किया जाएगा।

ज्ञातव्य रहे कि, ई.डी. ने हेमंत सोरेन के नई दिल्ली में शांति निकेतन स्थित आवास से सोमवार को ही 36 लाख रुपए कैश, एक बीएमडब्ल्यू कार और कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। ई.डी. ने उनसे इसके बारे में कई सवाल पूछे, सोरेन ने इस बात से इन्कार किया कि कैश और कार उनकी है। इसके अलावा रांची के बड़गाई अंचल की करीब चार एकड़ जमीन के स्वामित्व को लेकर पूछे गए सवालों पर सोरेन के जवाब से ई.डी. के अफसर संतुष्ट नहीं हुए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री आवास, ई.डी. कार्यालय, राजभवन, भाजपा कार्यालय सहित रांची के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

आई.पी.एस. राजीव कुमार शर्मा ए.सी.बी. के नए डी.जी. बने

राज्य सरकार ने 13 आई.पी.एस. अधिकारियों के तबादले किए

■ गौरव श्रीवास्तव मुख्यमंत्री सुरक्षा में और राजेन्द्र सिंह को जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया।

■ कोटा, जोधपुर और भरतपुर रेंज आई.जी. भी बदले।

जयपुर, 31 जनवरी। राज्य सरकार ने बुधवार को फिर 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें आईपीएस राजीव कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नया डीजी नियुक्त किया गया है। सरकार ने काफी लंबे समय बाद एसीबी में डीजी की नियुक्ति की है। इसके अलावा 11 आईजी और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को भी बदला है।

आदेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक, लॉ एंड ऑर्डर, राजीव कुमार शर्मा को एसीबी में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, आईजी गौरव श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। उनका तबादला आईजी मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं मुख्यमंत्री सर्तकता के पद पर किया गया है। आईपीएस राजेन्द्र सिंह को जोधपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आईपीएस रवि दत्त गौड़ का जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद से तबादला कर कोटा रेंज आईजी लगाया गया है।

इसके अलावा आईपीएस विकास कुमार को जोधपुर रेंज आईजी और राहुल प्रकाश को भरतपुर रेंज आईजी तथा आईपीएस ओमप्रकाश द्वितीय को डीआईजी पाली रेंज के पद पर लगाया गया है।

आईपीएस अंशुमन भोमिया को आईजी एटीएस जयपुर, प्रसन्न कुमार खमेसरा को आईजी सीआईडी क्राइम ब्रांच, एचजी राघवेन्द्र सुहासा को आईजी रेलवे, हिंगलाजदान को आईजी पुलिस रूल्स, जय नारायण को आईजी इंटेलिजेंस और अनिल कुमार टांक को आईजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय जयपुर के पद लगाया गया है।

राज्यपाल ने राज्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूर्व कन्नड़ के संकेतक विशेष रूप से लगाने होंगे।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार के आदेश की पालना के लिए दो माह का समय दिया गया था। कन्नड़ लैंग्वेज कम्प्रीहैन्सिव डवलपमैंट एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को कर्नाटक मंत्रिमण्डल ने एक माह पूर्व मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमण्डल ने संशोधन पर स्वीकृति के साथ ही उक्त निर्णय लिया था। लेकिन कर्नाटक के राज्यपाल इस मामले में राज्य सरकार से सहमत नहीं हुए और यह मत भिन्नता अब सार्वजनिक हो चुकी है।

संयोगवश, तमिलनाडू की जनता ने हिंदी थोपने के विरोध में कई बार विरोध प्रदर्शन किए हैं और कर्नाटक में भी जो अब कर्नाटक में कन्नड़ भाषा के प्रभुत्व का आंदोलन बनता दिख रहा है।

राज्यपाल द्वारा अध्यादेश निरस्त किए जाने पर जोर देते हुए, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर से उठाया जाएगा।

शिव कुमार ने कहा कि "राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को निरस्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राज्य सूची का विषय है तथा कन्नड़ भाषा हमारी पहचान एवं प्रतिष्ठा है। मैं राज्यपाल से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूँ। यह एक प्रगतिशील सोच है तथा इसे लेकर एक कानून भी अस्तित्व में है। किसी राजनीतिक पार्टी अथवा नागरिक ने इस पर आपत्ति नहीं जतायी। हम इसे विधानसभा में पारित करेंगे। इसे 15 दिनों के भीतर लौटाना राज्यपाल के लिए उचित नहीं था।"

कर्नाटक के कन्नड़ एवं संस्कृति राज्यमंत्री शिवराज तांगादगी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उन्हें गवर्नर से इसकी फाइल प्राप्त हुई है। राज्यपाल ने फाइल वापस लौटाने का कारण "विधानसभा सत्र" लिखा। मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। यह भाषा के गर्व को लेकर है। मैं विधानसभा सत्र के दौरान इसे सदन के पटल पर रखूंगा और फिर इसे राज्यपाल के पास भेजूंगा। मैं बुधवार को राज्यपाल से भेंट करना चाहता था, क्योंकि मैं अन्य जिलों के दौरे पर था। पर उन्होंने फाइल लौटा दी।"

16वें वित्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। डॉ. निरंजन राजाध्यक्षा, जो अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक हैं। चौथे अंश-कालिक सदस्य डॉ. सौम्य कांति घोष हैं जो भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप चीफ इकोनोमिक एडवाइज़र हैं।

आयोग को अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत करनी हैं, इसमें 1 अप्रेल 2026 से आगामी पांच वर्षों के लिए सिफारिशें पेश की जाएंगी।

'अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय बनने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिखित एक पुस्तक का हवाला देते हुए धवन ने बैंच से कहा कि, बहस का कोई अन्त नहीं हैं, इसलिए हम इतिहास की बात भी कर सकते हैं तथा सुनवाई के दौरान वास्तव में ऐसा ही हुआ है। एक पक्ष वह कह रहा है जो वो मानता है अल्पसंख्यक दर्जा त्याग दिया गया था हम यह बताना चाहते हैं कि उस समय मनोस्थिति क्या थी, जैसा कि ए.एम.यू. एक्ट 1920 और उसकी पृष्ठ भूमि में स्पष्ट किया गया है। इस मुद्दे पर मंत्री का संबोधन सलैक्ट कमेटी की प्रक्रिया और संसद में चली बहस प्रासंगिक है।

इससे पूर्व ए.एम.यू. को अल्पसंख्यक हर्जा देने का विरोध करने वाले प्रतिवादियों की ओर से पेश कई वकीलों ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि ए.एम.यू. का गठन ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1920 में एक केन्द्रीय अधिनियम के तहत हुआ था, इसलिए वह अल्पसंख्यक दर्जे की मांग नहीं कर सकता।

7 जजों की एक संविधान पीठ शीर्ष अदालत के वर्ष 1981 और 2019 के रैफरेंस सहित ए.एम.यू. के अल्पसंख्यक दर्जे के सम्बन्ध में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। रैफरेंस में पांच जजों की एक संविधान बैं द्वारा वर्ष 1967 में दिए निर्णय के पुनरावलोकन की बात कहीं गई है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 1967 में अजीज़ बाशा केस में व्यवस्था दी थी कि, ए.एम.यू. एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, अत: अनुच्छेद 29 और 30 के तहत इसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। इससे पहले की सुनवाई में संविधान बैंच को बताया गया था कि, भोपाल की महारानी सुल्तान जहां बेगम दिसम्बर 1920 से मई 1930 तक ए.एम.यू. की पहली चांसलर रही और ए.एम.यू. की एग्ज़ीक्युटिव काउन्सिल, एकेडैमिक काउन्सिल, टीचिंग फैकल्टी से लेकर क्लासरूम्स तक मुस्लिमों की मौजूदगी 82 से 85 प्रतिशत है। कोर्ट को बताया गया कि ए.एम.यू. एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में वह वहीं करता है जो संविधान के अनुछेद 30 (1) के अन्तर्गत करना चाहिए।

गुलज़ार का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लॉन में ही यतेन्द्र मिश्रा और सत्य सारण के साथ दोपहर 1 बजे चर्चा करेंगे। गुलज़ार के जयपुर पहुंचने की खुशी में उनके एक प्रशंसक ने स्कैच बनाया है, जो यहां प्रकाशित है।

ब्रॉडकास्टिंग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक कि सोशल प्लेटफार्म और इसके साथ ही न्यूज़ वैबसाइट्स पर भी अपना नियंत्रण बढ़ा रही है।

इस विधेयक के बारे में उनका कहना है इस विधेयक में पत्रकारिता एवं सामग्री निर्माण (कंटेन्ट क्रिएशंस) के अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया है और इसकी परिभाषा जानबूझ कर इतनी विस्तृत कर दी गई है कि ब्रॉडकास्ट एवं डिजिटल मीडिया दोनों को मिलाने के बाद समस्त प्रकार के ऑन लाइन मीडिया को नियंत्रित किया जा सकता है, हालांकि ब्रॉडकॉस्ट मीडिया में बड़े चैनल्स के साथ ही एक या दो व्यक्तियों द्वारा संचालित छोटे चैनल्स भी शामिल हैं।

समाचार संगठनों में दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स व पत्रकारों का राष्ट्रीय गठबंधन शामिल है ने कहा कि इस विधेयक को मीडिया कमीशन ऑफ इंडिया जैसे एक सामान्य निकाय के गठन होने तक रोके रखा जा सकता था जिसमें सरकारी नियंत्रण के समस्त पहलुओं का परीक्षण करने के लिए विषय विशेषज्ञों एवं हितधारकों को सम्मिलित किया जा सकता था। वे चाहते हैं कि इस विवादास्पद बिल को तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि यह मीडिया स्वामित्व की एकाग्रता पर अशुभ रूप से चुप है जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व वैचारिक भिन्नता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

कौन किसकी मदद कर रहा है ...

■ इस शृंखला में यह भी तर्क दिया जा रहा है कि, खड़गे का नाम इण्डिया गठबंधन के कन्वीनर के रूप में प्रस्तावित करके ममता जी ने इण्डिया गठबंधन में फूट पैदा की और नीतीश को एन.डी.ए. जॉइन करने को मजबूर किया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गिरफ्तार करने आयी थी। ई.डी. अधिकारी व अन्य लोग जो शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने आए थे उन्हें स्थानीय लोगों ने बुरी तरह पीटा, इन लोगों को शाहजहां ने एकत्रित किया था। इस घटना के 25 दिन बाद भी शेख शाहजहां पुलिस की पकड़ से दूर है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कहते हैं कि आत्मसमर्पण का मात्र एक सम्मन ही उसे पुलिस के घेरे में ला सकता है। जब सी.बी.आई. और ई.डी. ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को त्याग पत्र दिए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया तब विपक्षी नेताओं ने कहा "देखो विरोधाभास।" तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी अड़चन डाली। बुधवार को कुछ लोगों ने राहुल की कार पर पत्थर फेंके जिससे पीछे का शीशा टूट गया।

राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेसी नेता व पदाधिकारी इस तरह हताश है कि उन्होंने इस घटना को यह कह कर हल्का करने की कोशिश की कि, कार के ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से विंडस्क्रीन टूटी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अवश्य तृणमूल के लोगों पर हमले का आरोप लगाया। यात्रा पर प्रशासनिक प्रतिबंध के कारण राहुल को न्याय यात्रा का रूट बदलना पड़ा।

इसी बीच ममता बनर्जी ने उत्तरी बंगाल के उन क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया, जहां राहुल अपनी यात्रा ले जाने वाले थे। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल की कार पर हमला बिहार में हुआ था, जिसका अधीर रंजन ने जोरदार खंडन किया।

ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में दरारें डालने के लिए दो तरह की भूमिकाएं निभा रही हैं जो अब जगजाहिर हो गई है। वे विपक्षी दलों के अभियान में अडंगा लगा रही हैं। दूसरे वे बंगाल में कांग्रेस का जोरदार विरोध कर रही हैं और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की हरेक कोशिश का विरोध कर रही हैं।विपक्षी गठबंधन के शुरूआत में जो दरारें उभरी, उसमें तृणमूल खासकर ममता बनर्जी की भूमिका पर दो दलों ने सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने ही कहा था कि तृणमूल लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी।

ममता बनर्जी की हरकतों ने विपक्षी गठबंधन को कमजोर बनाया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में उठाया जिसकी वजह से नीतीश गठबंधन से बाहर हो गये थे। तृणमूल की हिंसा झेलने वाले वामपंथी व कांग्रेसी बंगाल में तृणमूल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये सभी दल एकजुट होने को तैयार है। यह है बंगाल में विपक्षी दलों की एकजुटता की हताशा भरी तस्वीर।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908